# 2,817 करोड़ के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी

## कैबिनेट फैसले : किसानों को सौगात, आय बढ़ाने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए पहल

अमर उजाला ब्यूरो

**नई दिल्ली।** किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें एक और सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 13,966 करोड़ रुपये की सात योजनाओं को मंजूरी दी। इससे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें 2,817 करोड़ रुपये के निवेश से डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना भी शामिल है।

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि कैबिनेट बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और आय बढ़ाने के लिए सात बड़े फैसले किए गए। इनमें पहला डिजिटल कृषि मिशन है।

इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमें सफलता भी मिली है। उसी आधार पर 2,817 करोड़ रुपये के कुल निवेश से डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी।

इसके अलावा खाद्य, पोषण सुरक्षा के लिए 3,979 करोड़, 2,291 करोड़ की कृषि शिक्षा, प्रबंधन योजना, 860 करोड़ की बागवानी योजना, 1,702 करोड़ पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन, उत्पादन योजना, कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत करने के लिए 1,202 करोड़ की योजना और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दी स्वीकृति, मुंबई-इंदौर रेल लाइन पर मुहर

**1,202**
करोड़ की लागत से कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण

**1,115**
करोड़ रुपये के खर्च के साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

### डिजिटल कृषि मिशन में दो आधारभूत स्तंभ

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के आधार पर डिजिटल कृषि मिशन किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। इसमें मृदा प्रोफाइल, डिजिटल फसल अनुमान जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल है। मिशन का कुल खर्च 2,817 करोड़ रुपये है। इसमें दो आधारभूत स्तंभ शामिल हैं। पहला कृषि स्टैक है, जिसमें किसान रजिस्ट्री, ग्राम भूमि मैप रजिस्ट्री, फसल बोई रजिस्ट्री शामिल है। दूसरा कृषि निर्णय सहायता प्रणाली है जिसके तहत भूस्थानिक डाटा, सूखा-बाढ़ निगरानी, मौसम-उपग्रह डाटा, भूजल-जल उपलब्धता, फसल उपज और बीमा के लिए मॉडलिंग शामिल है।

### खाद्य व पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान

3,979 करोड़ रुपये की लागत वाली यह पहल किसानों को जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार करेगी और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी। अनुसंधान व शिक्षा, पौध आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य, चारा फसल के लिए आनुवंशिक सुधार, दलहन व तिलहन फसल सुधार, वाणिज्यिक फसलों में सुधार, कीटों, परागणकों पर शोध इसके स्तंभ हैं।

**सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन :** 1,702 करोड़ रुपये की योजना का उद्देश्य पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है। इसमें पशु स्वास्थ्य प्रबंधन व पशु चिकित्सा शिक्षा, डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास, पशु आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, उत्पादन व सुधार, पशु पोषण व छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का उत्पादन व विकास शामिल है।

### कृषि शिक्षा, प्रबंधन मजबूत करना लक्ष्य

2,291 करोड़ रुपये के कुल खर्च के साथ यह योजना कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कृषि अनुसंधान व शिक्षा का आधुनिकीकरण, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, नवीनतम तकनीक का उपयोग करें जैसे डिजिटल डीपीआई, एआई, बड़ा डेटा, रिमोट और प्राकृतिक खेती और जलवायु लचीलापन।

### बागवानी के सतत विकास के लिए 860 करोड़ रुपये

860 करोड़ रुपये लागत की योजना का मकसद बागवानी पौधों से किसानों की आय बढ़ाना है। इसमें उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण बागवानी फसलें जड़, कंद, सब्जी, फूलों की खेती, मशरूम की फसलें, औषधीय पौधे शामिल हैं।

## गुजरात में एक और सेमीकंडक्टर संयंत्र, रोजाना बनेंगे 63 लाख चिप

**नई दिल्ली।** गुजरात के साणंद में एक और सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित होगा। इस संयंत्र में प्रतिदिन 63 लाख चिप का उत्पादन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सोमवार को केन्य सेमीकॉन प्रा. लि. के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए 3,307 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित हो रहा है।

केन्स का साणंद में संयंत्र 46 एकड़ में बनेगा। उत्पादन का बड़ा हिस्सा केन्स इंडस्ट्रीज को जाएगा। इसकी बुकिंग पहले ही हो चुकी है। यह संयंत्र बिजली क्षेत्र से संबंधित चिप की भी आपूर्ति करेगा। कंपनी ने इस परियोजना के लिए साणंद में पहले ही जमीन का अधिग्रहण कर लिया है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ब्यूरो